UPSC Daily Current Affairs 17 AUG 2021

ई-आपातकालीन X-Misc वीज़ा

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारत के गृह मंत्रालय ने 'ई-आपातकालीन X-Misc वीज़ा' कहलाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की नई श्रेणी की घोषणा की है। इसे भारत में अफगानों के प्रवेश के लिए वीज़ा आवेदनों के तेजी से निपटारे के लिए लागू किया गया है।

ई-आपातकालीन X-Misc वीज़ा के बारे में जानकारी

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य उन अफगानों के आवेदनों को तेजी से निपटारा करना है जो अफगानिस्तान में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से भारत में आना चाहते हैं।
- MHA अफगानिस्तान में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से वीज़ा प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है।

नोट:

- विदेश मंत्रालय ने युद्ध से पीड़ित देश से स्वदेश आगमन और अन्य अनुरोधों के समन्वय के लिए एक विशेष अफगानिस्तान एकक की भी स्थापना की है। अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद खराब हो गई है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

बीमाकृत व्यक्ति योजना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक सुरक्षा, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कोविड-19 की वजह से मौत के मामले में ESI बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए **बीमाकृत व्यक्ति योजना** की अधिसूचना जारी की है।

बीमाकृत व्यक्ति योजना के बारे में जानकारी

- यह कोविड-19 की वजह से मृत्यु के मामले में ESI बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए एक योजना है।
- यह योजना न्यूनतम रु. 1,800 प्रतिमाह प्रदान करेगी।

लाभकर्ता

- यह योजना उन बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को कवर करेगी जिनका कोविड-19 की पहचान होने के कम से कम तीन महीने पूर्व ESIC पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है और साथ ही वे पॉजीटिव होने की तिथि पर नौकरी में हैं।
- कोविड-19 से मृत्यु होने के मामले में, पति अथवा पत्नी, 25 वर्ष तक की आयु के पुत्र, गैरविवाहित पुत्री और बीमाकृत व्यक्ति की विधवा मां राहत के लिए पात्र होंगे।
- **यह योजना जो 24 मार्च, 2020 से दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी, बीमाकृत व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन के 90% तक को प्रदान करेगी जिसका आश्रितों को भुगतान किया जाएगा।**

सरकारी योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 2024 तक फोर्टीफाइड किया जाएगा

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र और शासन, स्रोत- लाइवमिंट)

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टीफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

चावल के फोर्टीफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत इसके वितरण के बारे में जानकारी

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने केंद्रीय प्रायोजित पायलट योजना के तहत चावल के फोर्टीफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा इसके वितरण की स्वीकृति दे दी है।

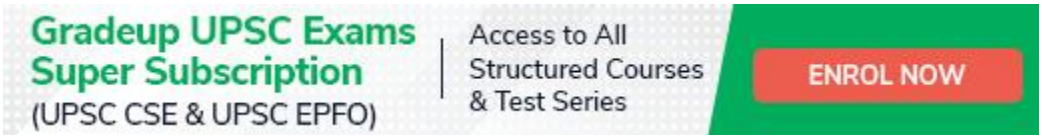

- इस योजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति दी गई थी और 2019-20 से तीन वर्षों के लिए रु. 174.6 करोड़ का बजट आवंटन प्रदान किया गया है।

वित्तीय सहायता

- इस योजना का भारत सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व, पर्वतीय और द्वीपीय राज्यों के संदर्भ में 90:10 और बाकी के राज्यों के संदर्भ में 75:25 के अनुपात में वित्त पोषण किया जा रहा है।
- आगे, सरकार ने सभी राज्यों को सलाह भी दी है और PDS के द्वारा फोर्टीफाइड आटे के वितरण के लिए कहा है।
- **यह पायलट योजना 15 जिलों पर केंद्रित है, विशेष रूप से प्रति राज्य 1 जिले पर।**
- अभी तक, 15 राज्यों, अर्थात, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने पाइलट योजना के क्रियान्वयन पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है।
- इन राज्यों में से, महाराष्ट्र और गुजरात ने फरवरी 2020 से पाइलट योजना में PDS के तहत फोर्टीफाइड चावल के वितरण की शुरुआत कर दी है।

क्रियान्वयन में देरी

- 15 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फोर्टीफाइड चावल के वितरण की वर्तमान पायलट योजना का क्रियान्वयन केवल अभी तक 5 जिलों में किया गया है, यद्यपि इस परियोजना की आधी से ज्यादा अवधि बीत चुकी है।
- ये पांच राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़।
- बाकी के 10 राज्यों ने अब जाकर अपने विभिन्न जिलों की पहचान की है, और जल्दी ही वितरण शुरू करेंगे, लेकिन योजना की अवधि में डेढ़ वर्ष से भी कम समय बाकी है।

ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र और शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम' को झंडी दिखाएगा, जो **सियाचिन ग्लेसियर** पर चढ़ने का विश्व कीर्तिमान होगा।

ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के एक दल को सियाचिन ग्लेसियर पर चढ़ने की अनुमति दी है।
- पूरे देश से दिव्यांगों में से चुने हुए लोगों को सैन्य बलों के सेवानिवृत्त लोगों की एक टीमः टीम CLAW द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- ये चुने हुए व्यक्ति कुमार पोस्ट (सियाचिन ग्लेसियर) तक एक अभियान में भाग लेंगे जिसका उद्देश्य विश्व के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र में पहुँचने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सबसे बड़ी टीम द्वारा एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करना है।
- इसका लक्ष्य दिव्यांग व्यक्तियों की अपार सृजनात्मक संभावना का उपयोग करना है।

महत्व

- यह अभियान विश्व के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र में पहुंचने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सबसे बड़ी टीम द्वारा एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगा।
- यह भारत को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अग्रणी के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित कर देगा।
- यह अन्य देशों को अनुकरण करने के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित करेगा।

TAPAS (उत्पादकता और सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण)

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र और शासन, स्रोत-PIB)

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री ने TAPAS (उत्पादकता और सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है।

TAPAS पोर्टल के बारे में जानकारी

- यह एक मानक MOOC (विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम) प्लेटफॉर्म है जिसमें फिल्म्ड व्याख्यान और ई-अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री शामिल हैं।

TAPAS के बारे में जानकारी

- यह एक मानक MOOC (विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम) प्लेटफॉर्म है जिसमें फिल्म्ड व्याख्यान और ई-अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री शामिल हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- यह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) की पहल है।

लक्ष्य

- इसका लक्ष्य विषय के विशेषज्ञों, अध्ययन सामग्री और ज्यादा के द्वारा व्याख्यानों तक पहुँच को उपलब्ध कराना है, लेकिन इसे इस तरह से होना चाहिए कि यह बिना अध्यापन की गुणवत्ता के साथ समझौता किए हुए भौतिक कक्षा का संपूरक सिद्ध हो।

उद्देश्य

- पाठ्यक्रम मॉड्यूल को लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण प्रदान करना और भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान और कौशलों को उन्नत करना है।
- इसे किसी के द्वारा भी किया जा सकता है जो विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है और इसमें शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

शामिल पाठ्यक्रम

यह पांच मूलभूत पाठ्यक्रम प्रदान करेगा

a. मादक द्रव्य सेवन रोकथाम,
b. वृद्धों की देखभाल,
c. मतिभ्रंश वाले व्यक्ति की देखभाल और प्रबंधन,
d. विपरीतलिंगियों के मामले,
e. सामाजिक रक्षा मामलों पर समग्र पाठ्यक्रम।

इंडिगऊः भारत की पहली मवेशी जिनोमिक चिप

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत-AIR)

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने हाल में "इंडिगऊः भारत की पहली मवेशी जिनोमिक चिप" को जारी किया है।

इंडिगऊ के बारे में जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

Conservation of cows

- इसका विकास राष्ट्रीय पशु बायोतकनीक संस्थान (NAIB), हैदराबाद ने किया है जो **बायोतकनीक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।**
- इंडिगऊ विशुद्ध रूप से देशी और दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी चिप है।

महत्व

- इस चिप की बेहतर गुणों के साथ मवेशी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी योजनाओं में व्यावहारिक उपयोगिता होगी।
- **यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के कार्य में भी मदद देगी।**
- यह गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोले इत्यादि जैसी देशी मवेशी नस्लों की विशुद्ध प्रकारों के संरक्षण में मदद देगी।

कारेज़ प्रणाली

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- डाउन टू अर्थ)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, अफगानिस्तान के लोग तालिबान द्वारा प्रांतीय राजधानियों साथ ही साथ अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर कब्जा करने के बाद कारेज़ प्रणाली के बारे में चिंतित हैं।

कनात/कारेज़ प्रणाली के बारे में जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

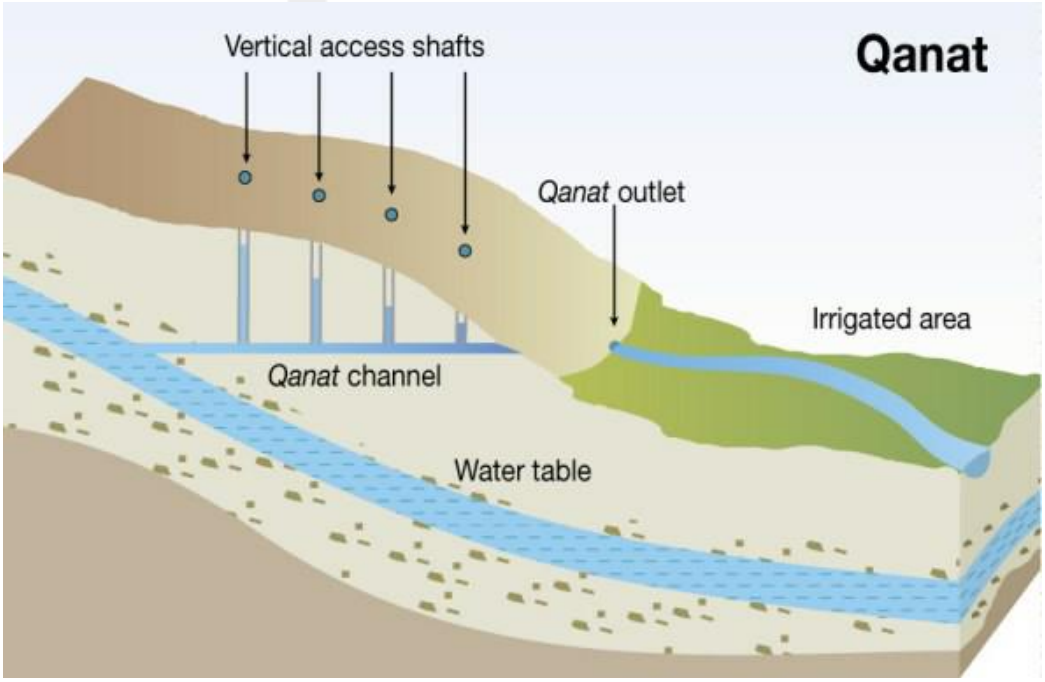

- यह जल संचय तकनीक है जिसका जन्म ईरान/पर्सिया में हुआ था।
- यह जल्दी ही पर्सिया, अरब और तुर्की भूमियों में फैल गई।
- **यह भारतीय उपमहाद्वीप में भी 800 वर्ष पुराने इस्लामी काल के दौरान भारत में आई।**
- कारेज़ तकनीक भूमिगत जल स्रोतों (अथवा प्राकृतिक सोतों) का दोहन करती है और बस्तियों में एक भूमिगत सुरंग के द्वारा जल को भेजती है, जिसका अंत विभिन्न प्रयोगों के लिए गांव में सतह की नहर में और/अथवा तालाबों में होता है।

कारेज़ और अफगानिस्तान

- कारेज़ प्रणाली अफगानिस्तान में 8 प्रतिशत सिंचित भूमि को कवर करती है।
- यह अफगानिस्तान के दक्षिणी और दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रों में बहुसंख्यक ग्रामीण समुदायों के लिए जल का एकमात्र स्रोत है।
- विश्व भर में कारेज़ 38 देशों में पाया जाता है और इनमें से अधिकांश मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित हैं।

भारत और कारेज़ प्रणाली

- भारतीय उपमहाद्वीप में कारेज़ प्रणाली को बहमनी सल्तनत के दौरान लाया गया था, जिसके संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह थे।
- बाद में इसका पांच अन्य सल्तनतों में विभाजन हो गयाः बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बेरार।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- कुट्टी जिन्होंने कर्नाटक के कारेज़ों का अध्ययन किया है, ने भारत में पहली कारेज़ प्रणाली के सौंदर्य का वर्णन किया है जिसे बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली (1422-1436) के शासनकाल के दौरान बीदर शहर में निर्मित किया गया था। इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर हस्तांतरित की थी।
- 15वीं सदी तक, बीजापुर शहर में पाइपलाइनों का एक नेटवर्क था जिसके द्वारा सभी को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिलती थी।

जंगली गुलमेहंदी

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- शोधकर्ताओं ने हाल में केरल में जंगली गुलमेहंदी की तीन नई प्रजातियों की पहचान की है, जिसमें से दो का नामकरण पुराने कम्युनिस्ट और पूर्व मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के. के. शैलजा के नाम पर किया गया है।

जंगली गुलमेहंदी के बारे में जानकारी

- यह प्रजाति वंश इम्पेशेंस (परिवार बालसमीनेसेई) से संबंधित है।
- इन्हें वानस्पतिक सर्वेक्षणों के दौरान दक्षिणी केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र और इडुक्की जिले में देखा गया।
- इस वंश के पौधे मलयालम में 'काशीथुंबा' के नाम से लोकप्रिय हैं।

संरक्षण की स्थिति

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- सभी तीन प्रजातियों को IUCN लाल सूची के अनुसार **गंभीर रूप से खतरे वाली प्रजाति** (CE) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- वंश इम्पेशेंस को भारत में 210 से ज्यादा वर्गिकी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।
- **106 से ज्यादा प्रजातियां पश्चिमी घाट की स्थानिक हैं, जिसमें से 80% खतरे में हैं।**

आइवरी कोस्ट ने 26 वर्षों में पहला इबोला मामला घोषित किया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- डाउन टू अर्थ)

खबरों में क्यों है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोटे डि आइवरी ने 26 वर्षों में पहला इबोला का मामला घोषित किया है और 2021 में ऐसा करने वाला वह तीसरा अफ्रीकी देश बन गया है।
- दो अन्य देश गिनी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने भी 2021 में मामलों की जानकारी दी थी।

इबोला के बारे में जानकारी

- इबोला वायरस रोग (EVD) जिसे पूर्व में इबोला हिमोरेजिक बुखार कहा जाता था, मानवों में एक गंभीर और घातक रोग है।

संप्रेषण

- चिम्पैंजी, गोरिल्ला, फल वाले चमगादड़ों जैसे जंगली जानवरों से लेकर मानवों तक और तब यह मानव से मानव के बीच में संप्रेषण के द्वारा मानव जनसंख्या में फैलता है।
- ऐसा सोचा जाता है कि टेरोपोडिडेई परिवार के फल वाले चमगादड़ इबोला के प्राकृतिक वायरस अतिथि हैं।
- **यह वायरस यौन संपर्क के द्वारा भी फैल सकता है।**

कोटे डि आइवरी के बारे में जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW